पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

1573. **श्री अजीत जोगी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना और कितने मूल्य का पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या विश्व बाजार में पटसन से बनी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और क्या इसके परिणामस्वरूप निर्यातकर्ता देशों की औसत यूनिट आमदनी में भी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या प्रमुख पटसन उत्पादक देशों के मध्य पटसन के उत्पादन, निर्यात और निर्यात-मूल्य को नियमित करने के लिए कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए पटसन के सामान की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है:--

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	मूल्य (रु० करोड़)
1989-90	2.37	296.40
1990-91	2.19	298.37
1991-92	2.37	387.24

(स्रोत : पटसन आयुक्त का कार्यालय)

(ख) पटसन के सामान के विश्व निर्यात में, जोकि वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान औसत 11.05 लाख टन थे घटकर वर्ष 1991-92 के दौरान 9.42 लाख टन के स्तर तक आ गए। निर्यातक देशों के औसत इकाई उपार्जन में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) : जी नहीं।

Lack of working capital and supply of Raw Cotton to NTC (Eastern Region)

1574. DR. SANJAYA SINH : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether thousands of employees of the National Textile Corporation (Easter Region) are in fear of losing their jobs due to lack of working capital and supply of the prime input-raw cotton;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) to (c) No Sir. However, Government have approved a Turn Around Strategy for NTC mills which, inter-alia, envisages rationalisation of workers, staff and officers through Voluntary Retirement Scheme and provision of interim liquidity to enable NTC to tide over the period of transition.

उत्तर प्रदेश को सूत की आपूर्ति

1575. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम उत्तर प्रदेश को सूत की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में सूत की मांग कितनी थी और निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सूत की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को सूत की अनियमित आपूर्ति से बुनकरों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सूत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) जी हां।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत प्रकार के उत्पादन को मद्दे नजर रखते हुए विभिन्न

राज्यों की सूत की आवश्यकता की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि यह मात्रा सूत के मूल्यों, कपड़े की निकासी और विभिन्न आर्थिक व अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की सूत की आवश्यकता निजी स्रोतों के अतिरिक्त राज्य अभिकरणों जैसे उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ द्वारा पूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय हथकरघा वस्त्र निगम भी इन अभिकरणों के सूत के कार्यकलापों में पूरा सहयोग देता है। गत 3 वर्षों के दौरान निगम ने उत्तर प्रदेश के अभिकरणों को निम्नलिखित सूत की मात्रा की आपूर्ति की :—

वर्ष	मात्रा (लाख कि०ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1989–90	11.97	477.44
1990–91	34.74	1478.40
1991–92	2.03	158.78
1992–93 (अप्रैल–अक्तूबर)	3.81	230.12

(ग) और (घ) ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति में कोई अनियमितता है। समस्या सूत के अधिक मूल्यों की है जिसके परिणामस्वरूप तैयार माल की निकासी में कमी आई है और हथकरघा अभिकरणों के उत्पादन अनुसूची में अस्थायी अव्यवस्था हुई है। उचित मूल्यों पर सूत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने चालू वर्ष में मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक योजना घोषित की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम 1992–93 में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हथकरघा अभिकरणों को 10 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति करेगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सहायता

1576. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कोई सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मिलवार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष सहायता राशि में कोई कटौती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989–90 से 1991–92 के दौरान एन० टी० सी० मिलों को उपलब्ध कराई गई बजट सहायता के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

बजट प्रावधान का उद्देश्य	वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1. नकदी घाटों की प्रतिपूर्ति	1989–90	287.11
	1990–91	97.00
	1991–92	73.00
2. आधुनिकीकरण	1989–90	20.00
	1990–91	20.00
	1991–92	शून्य
3. नियंत्रित कपड़ा उपदान	1989–90	10.00
	1990–91	10.00
	1991–92	21.83
4. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	1989–90	8.79
	1990–91	11.36
	1991–92	18.00

(ग) और (घ) एन० टी० सी० मिलों के लिए वर्ष 1992–93 के के दौरान किया गया बजट प्रावधान निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	प्रावधान का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
1.	नकदी घाटों की प्रतिपूर्ति	54.80
2.	आधुनिकीकरण	20.00
3.	नियंत्रित कपड़ा उपदान	15.00
4.	ब्याज उपदान	210.00